suitable replacement for Mr. Damodaran, who is currently running it. Mr. Damodaran is a very able Government servant. He will continue to run Unit-64 till such time he is given some other suitable assignment. But so far as Unit-II is concerned, for the first time, the best possible talent to run the Mutual Fund shall be found from the market.

श्री आर० पी० गोयनका: उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरे दो प्रश्न थे, जिसमें एक का तो अभी उन्होंने जवाब दे दिया है, निजीकरण के बारे में। तो वह तो मैं अब नहीं पूछ रहा हूं। दूसरा, मैं एक छोटा सा प्रश्न मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यूनिट ट्रस्ट को चार भागों में डिवाइड किया जा रहा है? और, अगर किया जा रहा है तो किस बेसिस पर किया जा रहा है?

श्री जसवंत सिंह: माननीय उपसभापति महोदया, चार भागों में विभाजन करने का, अभी तक कोई ऐसा सुना नहीं और न ही कोई हमारी योजना है। दो के विभाजन का संसद के सामने आकर हमने संसद को स्पष्ट रूप से बता दिया था—यूनिट-64 का एक तरफ और नेट असेट वेल्यू बेस्ड यूनिट-II का दूसरी तरफ। यह चार भागों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

भटिंडा तेल शोधन कारखाना

*3. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':†**
श्री लाजपत राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में भटिंडा स्थित तेल शोधन कारखाने का निर्माण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त तेल शोधन कारखाने के निर्माण पर अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है और अब तक इसका कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के विनिवेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो एचपीसीएल के विनिवेश के बाद उक्त तेल शोधन कारखाने का निर्माण कार्य पूरा करने का दायित्व किस एजेंसी को सौंपा जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

---

†सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) और (ख) पंजाब में भटिंडा में रिफाइनरी परियोजना का क्रियान्वयन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) की सहायक कंपनी गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार उक्त परियोजना पर संचयी व्यय 277.73 करोड़ रुपये है और भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य सहित वास्तविक प्रगति लगभग 5 प्रतिशत हुई है।

(ग) और (घ) सरकार ने एचपीसीएल के 34.01 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का विनिवेश करने और कर्मचारियों को एचपीसीएल के 5 प्रतिशत इक्विटी शेयर देने का निर्णय लिया है।

पंजाब में भटिंडा में रिफाइनरी परियोजना का क्रियान्वयन या तो एचपीसीएल द्वारा अथवा किसी उचित एजेंसी के माध्यम से सरकार द्वारा किया जाएगा।

Bhatinda Refinery

†*3. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':††
SHRI LAJPAT RAI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the oil-refinery at Bhatinda in Punjab is being constructed through Hindustan Petroleum Corporation Ltd.;

(b) if so, the details of amount spent so far on the construction of above refinery alongwith the percentage of the construction work completed, so far;

(c) whether it is also a fact that Government have accepted the proposal of disinvestment of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL); and

(d) if so, the name of the agency which would be entrusted with the responsibility of completing the construction of said refinery after the disinvestment of HPCL?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

Statement

(a) and (b) Refinery project at Bhatinda in Punjab is being implemented by Guru Gobind Singh Refineries Limited, a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL). As of 31.1.2003, cumulative expenditure on the project is Rs. 277.73 crore, and the physical progress including acquisition of land and construction work, is around 5%.

(c) and (d) The Government have decided to disinvest 34.01% of equity shares of HPCL through strategic sale and offer 5% of equity shares of HPCL to the employees.

The refinery project at Bhatinda in Punjab will either be implemented by HPCL, or the Government through an appropriate agency.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': उपसभापति महोदया, सरकार ने हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के स्ट्रेटिजिक सेल के माध्यम से विनिवेश का फैसला किया है और विनिवेश की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी है। अब एचपीसीएल की एक सहायक कंपनी गुरू गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड जो निर्माण कार्य कर रही थी और अभी भी कर रही है, जिसमें करीब-करीब 277.73 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन सरकार ने जो उत्तर दिया है भटिंडा रिफाइनरी के बारे में, उससे लगता है कि अभी तक भटिंडा रिफाइनरी के बारे में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। चूंकि सरकार ने गोल-मटोल जवाब दिया है, इसलिए हम सरकार से साफ-साफजानना चाहते हैं कि सरकार ने भटिंडा रिफाइनरी के बारे में क्या निर्णय लिया है?

श्री राम नाईक: उपसभापति महोदया, मैं साफ-साफ उत्तर देना चाहता हूं इस साफ-साफ प्रश्न के बारे में, कि भटिंडा रिफाइनरी जो है वह बनकर रहेगी।

उपसभापति: रिफाइन मीन्स साफ।

श्री राम नाईक: जी, मैडम।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैडम, लेकिन उत्तर में अथवा अथवा कहा गया है।

श्री राम नाईक: ऐसा है कि बनाने का जो फैसला हुआ है, वह चालू है और उसके तहत भटिंडा की रिफाइनरी बनेगी। जब एचपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट होना है तो उस समय एक बात साफ आती है कि रिफाइनरी का निर्माण कौन करे? उसमें यह सोचा गया है कि जो बिड्स मंगाई जाएंगी, उसमें यह भी बात रखी जाएगी और अगर बिड्स के माध्यम से या उस प्रकार से नहीं भी होता तो

सरकार कोई और दूसरा तरीका निकाल कर यह रिफाइनरी बनाएगी। एक बात निश्चित है कि नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल ने टेन्थ फाइव ईयर प्लान जो मंजूर किया है, उसमें भी यह रिफाइनरी है और इसलिए यह 9 मिलियन टन की, जिस पर 9,806 करोड़ रुपए की पूंजी लगने वाली है और जिसका रेट आफ रिटर्न 18.90 परसेंट है। यह अच्छी रिफाइनरी है और वह बनेगी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': उपसभापति महोदया, एचपीसीएल के विनिवेश का इन्होंने फैसला कर लिया और भटिंडा रिफाइनरी का निर्माण एचपीसीएल कर रही है, उस पर मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी जब विनिवेश होगा तो उस पर निर्णय लेंगे या फिर कोई अन्य इसको करेगा। तो मेरा कहना यह है कि इस पर सरकार साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं करती है कि उसको किसके माध्यम से बनाया जाएगा, सरकार एचपीसीएल के साथ उसका विनिवेश करेगी या फिर उसको किसी और माध्यम से बनाया जाएगा? इस पर सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए कि उसका निर्णय क्या है।

श्री राम नाईक: सरकार का निर्णय यही है कि एचपीसीएल के माध्यम से या अगर किसी कारण से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इस प्रकार की स्थिति अगर बनेगी तो फिर इसे सरकार बनाएगी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। मैडम, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है । विनिवेश नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। यह सरकार की सम्पत्ति है और अगर सरकार को अपनी सम्पत्ति को विनिवेश करना है तो सरकार अपनी किस सम्पत्ति का विनिवेश करे, इसका फैसला तो सरकार को ही करना पड़ेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are going to have a dicsussion on it, after the Special Mentions.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सम्पत्ति तो इनकी, विनिवेश वे करेंगे? सम्पत्ति तो एचपीसीएल की है, माननीय मंत्री जी साफ-साफ यह बताएं कि भटिंडा रिफाइनरी का काम एचपीसीएल के माध्यम से होगा या नहीं?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He needs a very refined answer.

लाला लाजपत राय: मैडम चेयरपरसन, यह बात सबकी जानकारी में है कि कुछ वर्ष पहले 10,000 करोड़ रुपये की कास्ट पर इस रिफाइनरी का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था और हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, जिस पर अब तक 300 करोड़ रुपए के करीब खर्च हो चुका है, लेकिन इस बीच में डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ गई है। अब डिसइन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा यह तो वही जानें लेकिन इस बैकग्राउंड में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या डिसइन्वेस्टमेंट के वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि यह

रिफाइनरी कम्पलीट की जाए और अगर कम्पलीट की जाएगी तो कब तक यह कम्पलीट की जाएगी।

श्री राम नाईक: उपसभापति महोदया, मैंने पहले ही कहा कि यह रिफाइनरी बनेगी। जिस रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधान मंत्री जी ने 13 नवम्बर, 1998 को किया था, उस पर काम चल रहा है, वह पूरा होगा। यह काम सामान्यत: 4 वर्षों में, 48 महीनों में पूरा करने का संकल्प है और दिसम्बर, 2006 में इसका मैकेनिकल कम्पलीशन होगा। इस प्रकार से इसके बारे में प्लानिंग की हुई है और उसी हिसाब से इसका काम चल रहा है।

लाला लाजपत राय: मैडम, मैंने यह प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि उत्तर में अनिश्चितता है यह करेगा, वह करेगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, यह लिखा गया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप बता दें कि लेट से लेट यह कब तक कम्पलीट हो जाएगा?

श्री राम नाईक: मैंने यह कहा कि दिसम्बर, 2006 तक बनने का प्रावधान है और उसके लिए जिस प्रकार से, जिस गति से काम चलना चाहिए, उस गति से और उस प्रकार से काम चल रहा है।

SHRI KULDIP NAYYAR: Madam, I am referring to part (c) of the question, "whether it is also a fact that Government have accepted the proposal of disinvestment". When the statement was made by the Cabinet, I think, the full advice of the Attorney-General was not mentioned. May I read out the full text of the advice of the Attorney-General? "My opinion is confined to the sole question whether there is any necessity of Parliamentary legislation or approval of Parliament for the, in principle, policy decision of investment, and not about the legal merits of form and contents of the acutal decision of investment in HPCL and BPCL." Will the hon. Minister tell us whether it is true or not?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Does your question relate to this refinery or disinvestment? If it is about disinvestment, we are going to have a full-fledged discussion on it.

SHRI KULDIP NAYYAR: This question will arise after the refinery has been built.

उपसभापति: वह तो अभी बनी ही नहीं है।

श्री कुलदीप नैयर: जब सवाल उठा है, यह सवाल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ रिफाइनरीज़ पर है, मैंने जो पूछा वह भटिंडा की रिफाइनरी के बारे में नहीं है, दूसरी रिफाइनरी के बारे में है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: But this question is, specifically, related to Bhatinda Refinery. So, I disallow your question.

Replacement of equipments at IGI airport

*4. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the imported equipment at Indira Gandhi International Airport for making the runway operational during fog conditions have failed to function during fog in December, 2002 and January, 2003;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) what was the cost of the equipments and whether there is replacement guarantee for these equipments; and

(d) what action is being taken to equip the airport with effective system/equipments for landing in foggy conditions?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN): (a) to (d) A Statement in this regard is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) No, Sir, The Instrument Landing System (ILS) equipment providing Category-IIIA operations during poor visibility for runway 28 at IGI Airport, Delhi has been working satisfactorily during the winters in December, 2002 and Jaunary 2003.

(c) and (d) The total cost of the Category-IIIA ILS alongwith its various components is Rs. 43 crores. Various components of ILS have varying warranty period between one to two years for defective supply/ works. The warranty for all such components is already over. The existing system is quite effective and many airlines have utilized it during fog/poor visibility conditions at IGI Airport, Delhi.

श्री राजकुमार धूत: आदरणीय उपसभापति महोदया, यदि सारा सिस्टम ठीक है तो इतनी उड़ानें क्यों रद्द करनी पड़ीं और मुसाफिरों को कष्ट क्यों झेलना पड़ा? इस सिस्टम में ठीक तरह से सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या सर्दियों में उड़ानों की यही हालत रहेगी? यदि हां, तो अगली सर्दियों में उड़ानों में समय की पाबंदी लाने के लिए क्या प्रबंध किया जाएगा?